'गुजरात से आया हूं... देश की नजर बिहार पर'

'डेवलपमेंट अर्बन इकानॉमिक्स ऑफ बिहार' पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में मौजूद मंत्री प्रेम कुमार, सचिव एस सिद्धार्थ, आद्री के सदस्य सचिव शैवाल गुप्ता, डीएफआईडी इंडिया के हेड सैम शार्प व अन्य।

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

'गुजरात से आया हूं.... पर, देश की नजर बिहार पर है। आज बिहार जो करेगा निश्चित रूप से कल देश करेगा।' 'डेवलपमेंट अर्बन इकानॉमिक्स ऑफ बिहार' पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के तकनीकी सत्र में एनआईयूए के डायरेक्टर चेतन वैद्य ने ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि बिहार का विकास सापेक्ष है और पूरी गंभीरता से इस पर काम हो रहा है। उन्होंने केन्द्र सरकार की जनुर्म योजना पर सवाल खड़े किए और कहा कि इसकी प्लानिंग में कई पक्षों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया।

कर्नाटक के पूर्व मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री के सलाहकार ए. रविन्द्र ने कहा कि शहरों के विकास की अलग-अलग योजना बनाने से बेहतर निष्कर्ष नहीं निकलने वाले। समेकित विकास के लिए स्थानीय स्तर पर तमाम योजनाओं को समबद्ध कर उसका कार्यान्वयन करना होगा। जिम्मेवारी के साथ लोकल लीडरशिप विकसित करनी होगी। आईपीई के डायरेक्टर डॉ. गंगाधर झा ने कहा कि यह हैरतअंगेज है कि गांव से अधिक गरीबी शहरों में है। शहरी विकास हमारी प्राथमिकता में नहीं है। हालांकि इसी वजह से शहरी क्षेत्र के विकास की संभावनाएं भी हैं। बियाडा के एमडी दीपक कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में औद्योगिक विकास की वास्तविक शुरूआत वर्ष 2006-07 से शुरू हुई। पर, अब वह निर्णायक दिशा में सकारात्मक रूप से बढ़ रहा है। दूसरे सत्र में पूर्व मुख्य सचिव व गुड गवर्नेंस के महानिदेशक नवीन कुमार ने कहा कि जिलों के विकास के साथ क्षेत्र के विकास की योजना बनानी चाहिए। कलस्टर बनाकर योजना बेहतर ढंग से कार्यान्वित की जा सकती है। सिडबी के महाप्रबंधक रामाकृष्णन ने कहा कि विकास की दौड़ में पूर्वी क्षेत्र का पीछे रह जाना दुखद है। पर, वहां संभावनाएं बनी हुई हैं। उन्होंने मॉडल फूड प्रोसेसिंग यूनिट व ग्रामीण क्षेत्र में रेस्टोरेंट को भविष्य की संभावना बताया। सीआईआई के बिहार चैप्टर के अध्यक्ष एस.पी. सिन्हा ने रिसॉर्स मैपिंग का सुझाव दिया तो चैम्बर ऑफ कामर्स के ओ.पी. साह विकास में जमीन की किल्लत को बड़ी बाधा बताया। टेरी यूनिवर्सिटी के प्रो. विनोद कुमार व नागपुर दाल मिल्स क्लस्टर प्रा. लि. के डायरेक्टर ने भी सिटी क्लस्टर डेवलपमेंट और इकोनोमिक कलस्टर की बात की।

विकसित बनेंगे बिहार के शहर

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

बोले मंत्री

- डेवलपमेंट अर्बन इकोनॉमिक्स ऑफ बिहार' पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित
- इस समय 55 शहरों के सिटी डेवलपमेंट प्लान पर हो रहा काम

बिहार के शहर भी देश के विकसित शहरों की श्रेणी में शामिल होंगे। सूबे के शहरों के विकास की कार्ययोजना पर काम शुरू हो चुका है। यह कहना है नगर विकास व आवास मंत्री डॉ. प्रेम कुमार का। वे 'डेवलपमेंट अर्बन इकानॉमिक्स ऑफ बिहार' पर शुक्रवार को आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के शहर आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में हैं, इसलिए इसके विकास की बेहतर योजना बनाई और कार्यान्वित की जा सकती है। कार्यशाला का आयोजन नगर विकास व आवास विभाग व एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट (आद्री) के संयुक्त तत्वावधान में डीएफआईडी संपोषित सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अरबन रिफार्म्स इन बिहार (स्पर) द्वारा किया गया।

मंत्री ने बताया कि गंदे, अविकसित और आर्थिक रूप से कमजोर शहर अब बीती बात होगी। राज्य के शहर हर दृष्टिकोण से सशक्त और बेहतर नागरिक सुविधाओं वाले होंगे। इस समय 55 शहरों के सिटी डेवलपमेंट प्लान पर काम हो रहा है और इन शहरों में तमाम नागरिक सुविधाओं का अत्याधुनिक तरीके से विकास होगा। यही नहीं स्पर कार्यक्रम के अंतर्गत सिटी बिजनेश प्लान भी बनाए जा रहे हैं। राज्य के लगभग 50 फीसदी शहर कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योग, 15 फीसदी शहर शैक्षणिक शहर और 11 प्रतिशत शहर पर्यटन आधारित शहरों के रूप में चिह्नित किए गए हैं। नगर विकास सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य के आर्थिक विकास को गति देने के लिए शहरी व नगरों की बदलती भूमिका की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार शहरों की योजना तैयार करने या फिर उन्हें मदद करने के पूर्व यह जानना आवश्यक है कि राज्य एवं शहरों की वर्तमान संस्थागत व रणनीतिक व्यवस्था इनकी जरूरतों के अनुरूप है या नहीं।

आद्री के सदस्य सचिव डॉ. शैबाल गुप्ता ने कहा कि बिहार में नगरीय विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं। सही रणनीति और कार्ययोजना से इस लक्ष्य को सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। इसके पहले स्पर के डॉ. नारायणन इडेडन ने बिहार के शहरी विकास की संभावनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। डीएफआईडी, इंडिया के हेड सैम शार्प ने बताया कि वे राज्य के शहरों के विकास के लिए हर संभव सहायता देंगे। फिलहाल डीएफआईडी के सहयोग से 29 शहरों के विकास की योजना पर काम हो रहा है।